बहुत सी जानकारी मिली। स्थानीय लोग कहते हैं कि हर महीने डेढ़ लाख रुपए का हफ्ता नीचे से ऊपर तक दिया जाता है, ताकि कोई इस illegal activity को नहीं रोके। ...(**व्यवधान**)... यह जो केस हुआ, उसमें हमने यह जानने की कोशिश की कि कौन यह गड्ढा करवा रहा था। यह मजदूर के खिलाफ नहीं होना चाहिए, तो यह FIR बनी। इस बार FIR बनी। इसमें 4 लोग दोषी हैं। इन 4 दोषी लोगों में से एक जो है, वह ब्लॉक पंचायत की स्टेंडिंग कमेटी का चेयरमैन है। जो नम्बर टू एक्यूज्ड है, वह नेता है और उसकी बीवी जिला परिषद् में मेंबर है और ...(**व्यवधान**)... यह हकीकत वहाँ दर्ज हुई FIR की है। ...(**व्यवधान**)... मैं अनुरोध करता हूँ कि इसको दूसरी तरह से मत लीजिए। जान की कीमत कोई भी मुआवजा नहीं दे सकता है। इंसान की जिन्दगी सबसे बड़ी कीमती है। हम सबको इसके लिए कंसर्न होना चाहिए कि एक गरीब, जो जान गँवाता है, उसके परिवार की क्या हालत होती है।

अत: मेरा अनुरोध है, माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके जरिए सरकार को कहना चाहता हूँ कि इसको लाइटली नहीं लें। यह एक घटना नहीं है। ऐसा बार-बार हो रहा है। अभी सिर्फ मैं देखता हूँ, कोई भी देख ले - अगर आप गूगल मैप खोल कर वहाँ की सैटेलाइट इमेज देखेंगे, तो आपको वहाँ जो गड्ढे और black spots दिखेंगे, वे सारे black spots चोरी वाले गड्ढे के हैं, वहाँ गलत तरीके से खुदाई हो रही है और वहाँ गरीब मजदूर अपनी जान गँवा रहा है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इसकी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी करवाए या सीबीआई से जाँच करवाए। चूँकि इसमें लोकल अथॉरिटी को हफ्ता जाता है, इसलिए यह ऐसे बंद नहीं होगा। मेरा आपसे यही अनुरोध है, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Shaktisinh Gohil: Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shrimati Priyanka Chatuvedi (Maharashtra), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu). Dr. Sasmit Patra (Odisha), Ms. Dola Sen (West Bengal), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri A.A. Rahim (Kerala).

Demand to allocate funds for pending public projects in the State of Tamil Nadu

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to bring to the attention of the Union Government through this august House that several important public projects in Tamil Nadu have been stalled due to the refusal of the Union Government to sanction the eligible and entitled funds.

Firstly, the Chennai Metro Rail Ltd., Phase-II Project, inaugurated by the hon. Union Home Minister in 2020, with a projected cost of Rs.63,246/- crores, has been pending for clearance and approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs for

the last three years. I request the hon. Union Finance Minister to allocate the accepted 50 per cent of the Project cost amounting to Rs.31,623/- crores expeditiously. Secondly, the Detailed Project Reports for the Coimbatore, Madurai and Tiruchi Metro Rail Projects have also been submitted to the Union Government and are pending approval for many months. Thirdly, with regard to the Tamil Nadu's request for releasing of Rs.37,907/- crores from the NDR Fund after the two natural calamities in last December, a mere Rs.276/- crores has been released by the Union Government. I request the hon. Union Home Minister to release at least Rs.3,000/- crores immediately as an interim measure to undertake restoration and relief works in Tamil Nadu. Fourthly, several dues from the Government of India are pending to be released to the Government of Tamil Nadu, including Rs.3,403/- crores to CMR subsidy and intra-State movement reimbursement, Rs.78/- crores towards Home Guards, Rs.188/- crores towards Railway Force, Rs.138/- crores towards Special Police Battalion at Tihar Jail and Rs.52/- crores towards ESI Scheme. Fifthly, for the Samagra Shiksha - Integrated Scheme for school education, the Project Approval Board has allocated Rs.3,533/- crores for the year 2023 and 2024 and Rs.3,586/- crores for the fiscal year 2024-25 to the State of Tamil Nadu with the Union Government contribution of 60 per cent. However, not even a single rupee is released. I take this opportunity to remind the hon. Union Finance Minister that India is a union of States and India's Constitution contemplates cooperative federalism between the States and the Union. The Union has to be fair in its fiscal allocation and devolution of funds to the States. Tamil Nadu and its people are being penalized for political reasons and receiving discriminatory treatment. The refusal of the Union Government to fund projects in Tamil Nadu and release owed funds is in violation of the Constitution and counter-productive. The hon. Union Finance Minister has to remember that Tamil Nadu's growth is India's growth. Therefore, through this august House, I urge the hon. Prime Minister to step in and direct the concerned Ministries to approve all the pending projects and release entitled funds due to Tamil Nadu without any further delay. Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri P. Wilson: Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri Tiruchi Siva (Tamil Nadu), Ms. Dola Sen (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri K.R.N. Rajeshkumar (Tamil Nadu), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Thank you, P. Wilson *ji*. Now, Shri Muzibulla Khan. Dr. Sasmit Patra will associate.

Demand for Special Category Status to the State of Odisha

श्री मुजीबुल्ला खान (ओडिशा) : उपसभापति महोदय, मैं ओडिशा राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के पक्ष में अपनी बात रखना चाहता हूँ। भारत की प्रगति तभी हो सकती है, जब राज्यों का विकास होगा। जब राज्यों का विकास होगा, तभी 'सबका साथ, सबका विकास' का जो नारा दिया गया है, वह फुलफिल हो सकता है। मेरे नेता नवीन पटनायक जी के बारे में भारतवर्ष के सारे लोग जानते हैं कि वे कितनी सिम्प्लिसिटी से रहते हैं और कितने सीधे-साधे इंसान हैं। उन्होंने चार जोड़ी कुर्ता-पायजामा और चार जोड़ी हवाई चप्पल से 25 साल ओडिशा राज्य में शासन किया। जब वे मुख्य मंत्री थे, तो वे बार-बार केन्द्र सरकार को ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में चिट्ठी लिखते थे। हमारे संसद सदस्य ने लोक सभा तथा राज्य सभा में इस विषय को उठाया, लेकिन केन्द्र सरकार ने अभी तक ओडिशा राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। हम समझते हैं कि इसके लिए एक तय क्राइटीरिया है, कुछ कानून हैं, कुछ नियम हैं, लेकिन किसी की भलाई के लिए इस कानून को बदला जा सकता है, इसमें अमेंडमेंट लाया जा सकता है। हमारे राज्य में 22 प्रतिशत ट्राइबल इलाका है, जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं। यह बैकवर्ड एरिया है और यह टूरिज़्म के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर है, प्रभु लिंगराज जी का मंदिर है, कोणार्क टेम्पल जैसा फेमस टेम्पल है, इसलिए यह टूरिज़्म के लिए भी जाना जाता है। सर, हमारे ओडिशा में 480 किलोमीटर की कोस्टल बेल्ट है ,जिसके कारण हमारे राज्य को बार-बार तूफान झेलना पड़ता है। महोदय ,इस कोस्टल बेल्ट में हमारे सात जिले आते हैं और वे हैं - गंजम ,खोरधा ,पुरी ,केंद्रपाड़ा ,जगतसिंहपुर ,भद्रक और बालासोर। जब 1999 में सुपर साइक्लोन आया था ,तब 10,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई थीं और 20,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए थे ,जिन्होंने अपने मां-बाप को खो दिया था। वर्ष 2000 में जब मेरे नेता नवीन पटनायक जी ओडिशा के मुख्य मंत्री बने और ओडिशा का शासन अपने हाथों में लिया ,तब उन्होंने इस बात के लिए कोशिश की कि साइक्लोन से कैसा निपटना है। सर ,वहाँ हर साल साइक्लोन आता है ,लेकिन मैं यहाँ कुछ प्रमुख साइक्लोन्स के बारे में बताना चाहता हूँ। फाइलिन 2013 में आया था ,हुदहुद 2014 में आया था ,तितली 2018 में आया था और फनी 2019 में आया था। सर ,आप जानते हैं कि नवीन बाबू हर वक्त ज़ीरो कैजुअल्टी के मामले में नंबर वन हैं और देश तो क्या ,विदेश के लोगों से भी उनको इस बात के लिए धन्यवाद मिला है कि वे ज़ीरो कैजुअल्टी में आगे बढ़ते हैं। ...(**समय की घंटी**)...सर ,यहाँ बीजेपी के अध्यक्ष ,नड्डा जी बैठे हैं, मेरा अनुरोध रहेगा, ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : धन्यवाद।

श्री मुजीबुल्ला खान : सर, मैं एक सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।